राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
State Level Bankers' Committee, Jharkhand

संयोजक : बैंक ऑफ़ इंडिया

पत्रांक संख्या : रा॰ स्त॰ बै॰ स॰ / 2023-24/598 दिनांक : 20.03.2024

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड के समस्त सदस्यों को पत्र

महोदय / महोदया,

विषय:- राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 86वीं त्रैमासिक (दिसम्बर 2023) समीक्षा बैठक की कार्यवृत्त

कृपया दिनांक 15.02.2024 को आयोजित राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखंड की 86वीं त्रैमासिक बैठक का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त बैठक की कार्यवृत्त एवं कृत कार्यवाही रिपोर्ट आपके सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न किया जा रहा है, साथ ही हम आप सभी को अवगत कराना चाहते हैं कि संलग्न कार्यवृत्त को राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति झारखंड की वेबसाइट (www.slbcjharkhand.in) पर भी उपलब्ध कराया गया है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया विभिन्न कार्य बिंदुओं पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए अद्यतन प्रगति हमें दिनांक 15 अप्रैल 2024 तक प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि तदनुसार आगामी बैठक में इनका समावेशन किया जा सके।

भवदीय,

उप महाप्रबंधक
राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
संगलन:- उपरोक्त अनुसार

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड
संयोजक: बैंक ऑफ इंडिया
दिनांक: 15-02-2024
स्थान– प्रोजेक्ट भवन- धुर्वा ,रांची

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 86वीं त्रैमासिक बैठक का कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, झारखण्ड की 86वीं त्रैमासिक बैठक दिनांक 15-02-2024 को सभागार -द्वितीय तल -प्रोजेक्ट भवन- धुर्वा ,रांची में आयोजित की गई। बैंक ऑफ इंडिया, प्रधान कार्यालय से कार्यपालक निदेशक श्री एम. कार्तिकेयन ने बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में राज्य सरकार की ओर से वित्त विभाग, झारखंड सरकार के सचिव, श्री प्रशान्त कुमार,भा०प्र० से०, एस०एल०बी०सी झारखंड के संयोजक बैंक, बैंक ऑफ इंडिया के महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार, भारतीय रिजर्व बैंक, रांची क्षेत्रीय कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक, श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह, नाबार्ड झारखंड क्षेत्रीय कार्यालय के मुख्य महाप्रबंधक, श्री सुनील कृष्णा जहागीरदार, एस०एल०बी०सी के उप महाप्रबंधक, श्री अनिल जगदीश जाधव, भारतीय रिजर्व बैंक, राँची क्षेत्रीय कार्यालय के उप महाप्रबन्धक श्री शमीम अंसारी उंपस्थित थे। इसके अतिरिक्त कैनरा बैंक के महाप्रबंधक श्री श्रीनाथ जोशी एवं अन्य सभी बैंकों के राज्य प्रमुख तथा सभी जिलों के अग्रणी जिला प्रबन्धक एवं केंद्र/राज्य सरकार के अन्य विभिन्न विभागों के वरीय अधिकारीगण भी बैठक में उपस्थित थे।

बैठक के क्रम मे सभा अध्यक्ष की अनुमति से विभिन्न मंचासीन गणमान्यों को सभा सम्बोधन हेतु आमंत्रित किया गया, जिनके अभिभाषण के मुख्य बिन्दु निम्नतः है-

क) राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के महाप्रबंधक श्री मनोज कुमार का सम्बोधन-

- श्री कुमार ने सभा सदस्यों को यह बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 की दिसम्बर तिमाही तक सभी बैंकों ने मिलकर झारखंड राज्य की अर्थव्यवस्था में कुल 75,815.87 करोड़ रुपये का ऋण प्रवाह किया है फलस्वरूप, राज्य में पहली बार कुल बकाया ऋण डेढ़ लाख करोड़ रूपय के आंकड़े को पार कर चुका है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

बैंकों का योगदान और बढ़ाया जा सके इसके लिए राज्य सरकार व अन्य हितधारकों से अपनी अपेक्षाओं से महाप्रबंधक एसएलबीसी ने सभा सदस्यों को अवगत करवाया।

- श्री कुमार ने बताया कि हमारे राज्य में CNT ACT, 1908 होने के कारण बड़े KCC, AIF एवं PMFME जैसे ऋण का उपभोग राज्य कि जनता नहीं कर पा रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऋण प्रवाह बढ़ाया जा सके इसलिए **Land Possession Certificate** के आधार पर दिये जा रहे के.सी.सी ऋण की सीमा 1 लाख से बढ़ा कर 1 लाख 60 हज़ार रुपय तक करने का आग्रह उन्होने राज्य सरकार से किया।

(एक्शन- राज्य सरकार)

- श्री कुमार ने बताया की सी.एन.टी/ एस.पी.टी के अंतर्गत आने वाले लोगों को कुछ मुट्ठी भर बैंक ही गृह ऋण प्रदान कर रहे हैं जिसकी राशि भी सीमित है। उन्होने राज्य सरकार से अनुरोध किया कि वह अधिनियम में आवासीय ऋण के वित्तपोषण के लिए कुछ संशोधन कर, छूट प्रदान की जाए और सी.एन.टी/ एस.पी.टी के अंतर्गत आने वाली संपत्तियों को गिरवी रखने की समयावधि को 05 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी जाये।

(एक्शन- राज्य सरकार)

❖ श्री कुमार ने बैंको के राज्य प्रमुख एवं सभी LDM से आग्रह किया कि कृपया हमारे राज्य में एक प्रतिशत ब्याज दर में मिलने वाली केसीसी फसल, पशुपालन व मत्स्य पालन ऋण के बारे में राज्य के किसानो, शाखाओं व बैंकिंग समन्वयक के बीच जागरूकता फैलायें। कृषकों को सही तरीके से केसीसी ऋण परिचालन करना सिखाएँ ताकि वे समयानुसार केसीसी ऋण का भुगतान कर इसका लाभ सही माने में उठा सकें।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक)

❖ महाप्रबंधक एस॰एल॰बी॰सी ने सदन को इस बात से अवगत कराया कि बैंकों के लिए RBI के दिशानिर्देश हैं कि, समायोजित नेट बैंक क्रेडिट (ए.एन.बी.सी) का 18% या ऑफ-बैलेंस शीट एक्सपोजर (सीईओबीई) के बराबर क्रेडिट, जो भी अधिक हो, कृषि क्षेत्र के लिए होना चाहिए, किन्तु राज्य के 27 बैंक इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाये हैं

उन्होने बैंकों से यह अनुरोध किया कि फसल, मत्स्य एवं पशुपालन हेतु KCC ऋण पर भी अपना ध्यान केन्द्रित करे जिससे 18% का आंकड़ा पार किया जा सके।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक)

❖ श्री कुमार ने सदन को जानकारी दी की शिक्षा ऋण के लिए CSIS योजना के तहत राज्य के बैंको द्वारा न्यूनतम claim हो रहा है। उन्होने सभी बैंकों के राज्य प्रमुख से अनुरोध किया कि इसके कारण का आत्मनिरीक्षण करें और सभी पात्र उम्मीदवारों को ब्याज सहायता प्रदान करने का प्रयास करें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्री कुमार ने सभा सदस्यों को बताया कि 31-03-2024 तक झारखंड राज्य के बचे हुए 22 ज़िलों को 100% digitalise करना है किन्तु 31.12.2023 तक 86.92% चालू खाते और 94.50% बचत खाते ही digitalise हो पाये हैं। उन्होने सभी बैंक प्रमुखों से अनुरोध किया कि वे अपनी शाखाओं को दिशानिर्देश दें कि सभी योग्य खातों को QR CODE/DEBIT CARD/AEPS/INTERNET BANKING इत्यादि से शत प्रतिशत digitalise करें।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्री कुमार ने कहा कि लोगों को साइबर धोखाधड़ी और फ़िशिंग जाल से सतर्क करना अत्यंत आवश्यकता है। सभी हितधारकों विशेषकर CFL ,FLC ,LDM से उन्होने आग्रह किया कि राज्य के कोने कोने में इस बारे में जागरूकता फैलाएँ ।

श्री कुमार ने पीड़ितों की मदद और सुरक्षा के लिए आर॰बी॰आई से आग्रह किया कि, police डिपार्टमेंट (CID) एवं अन्य हितधारकों के साथ मिलकर 24*7 फास्ट-ट्रैक तंत्र तैयार करने का प्रयास करें और बैंकों के लिए भी इस बावत उचित दिशानिर्देश जारी करने की कृपा करें।

(एक्शन- समस्त बैंक, अग्रणी जिला प्रबंधक एवं भारतीय रिजर्व बैंक)

❖ श्री कुमार ने Village Adoption Program Phase -2 के संदर्भ में सभा को अवगत कराया कि 31.12.2023 तक कुल 42% गोद लिए गये गाँवों को बैंकिंग सुविधा से संतृप्त किया जा चुका है । उन्होने सभी एल॰डी॰एम और बैंकों से आग्रह किया कि वे 31.03.2024 तक बचे सभी चिन्हित गाँवों को संतृप्त करें।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक)

अपने अभिभाषण के अंत में श्री कुमार ने RBI, राज्य सरकार, NABARD को उचित मार्गदर्शन एवं अन्य हितधारकों को परस्पर सहयोग के लिए धन्यवाद दिया और यह आश्वासन दिया कि आने वाले दिनों में

एस.एल.बी.सी के सभी हितधारक अपनी भूमिका को उचित तथा प्रभावी ढंग से निष्पादित करने मे अहम भूमिका अदा करेंगे।

ख) नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक श्री सुनील कृष्णा जहागीरदार का सम्बोधन-

- ❖ श्री जहागीरदार ने सर्वप्रथम सभी बैंकों को ऋण जमा अनुपात में बढ़ोतरी के लिए बधाई दी तत्पश्च्यात उन्होने 85वी एसएलबीसी में प्रधान सचिव श्री अजय कुमार सिंह द्वारा दिये गए उनके अभिभाषण का ज़िक्र करते हुए कहा कि श्री कुमार ने यह सुझाव दिया था कि एस.एल.बी.सी राज्य में ऋण जमा अनुपात कि बढ़ोतरी के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करे जिससे राज्य में ऋण प्रवाह को बढ़ाया जा सके।

(एक्शन- एस॰एल॰बी॰सी)

- ❖ नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने कहा कि 31.12.2023 तक प्राथमिकता क्षेत्र के लक्ष्य का 83 प्रतिशत हासिल कर लिया गया है, जिसमें कुल प्राथमिकता क्षेत्र की उपलब्धि में 69 प्रतिशत के साथ एम॰एस॰एम॰ई का प्रमुख योगदान है। उन्होंने आगे कहा कि अगर साल-दर-साल विकास पर नजर डालें तो शिक्षा, आवास, नवीकरणीय ऊर्जा और सामाजिक बुनियादी ढांचे के साथ एमएसएमई की हिस्सेदारी सबसे अधिक है।

  इसके आगे उन्होने बताया की इसके विपरीत, कुल बकाया में कृषि अग्रिम का हिस्सा प्राथमिकता क्षेत्र मानदंडों के तहत 18 प्रतिशत की अनिवार्य राष्ट्रीय अपेक्षा के मुकाबले सिर्फ 14 प्रतिशत है। उन्होंने बैंकों के राज्य प्रमुखों से कृषि क्षेत्र के विकास पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- ❖ श्री जहागीरदार ने नाबार्ड द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य फोकस पेपर के लॉन्च के बारे में सदन को जानकारी दी। उन्होंने आगे बताया कि PLP राज्य के सभी हितधारकों के परामर्श से तैयार किया गया है तथा वित्त वर्ष 2023-24 के लिए नाबार्ड द्वारा निर्धारित कुल प्राथमिकता क्षेत्र अनुमान Rs 43,726 करोड़ रुपये के मुकाबले, एसएलबीसी द्वारा निर्धारित ACP लक्ष्य Rs 47,985 करोड़ रखा गया था, जबकि दिसंबर तिमाही तक राज्य की उपलब्धि Rs 39,867.94 करोड़ थी, जो लक्ष्य का 83 प्रतिशत है।

  मुख्य महाप्रबंधक ने अपने वक्तव्य में कहा कि वित्त वर्ष 2024-25 के लिए प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम का अनुमान Rs 54,008.31 करोड़ रुपये है, जिसमें कृषि ऋण के लिए Rs.15,881 करोड़ रुपये, कुल कृषि के लिए Rs18,734 करोड़ रुपये, एमएसएमई के लिए Rs 28,043 रुपये और अन्य प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम के लिए Rs 7,230 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

- ❖ मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड ने crop loan के अंतर्गत राज्य में बैंको द्वारा दिसम्बर तिमाही तक के प्रदर्शन में अपनी नाराजगी जताई। उन्होने आगे बताया की चालू वित्त वर्ष में राज्य ने crop loan में केवल 2,375 करोड़ रुपये हासिल की है ,जो की लक्ष्य का मात्र 37 प्रतिशत है। उन्होने आगे बताया की राज्य ने दिसम्बर तिमाही तक कुल 3.20 लाख किसानों को crop loan के माध्यम से जोड़ा है। उन्होने राज्य के सभी बैंकों को इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्री जहागीरदार ने कहा कि चूंकि झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है और लगभग 15 लाख पीएम किसान लाभार्थियों के पास केसीसी ऋण नहीं है, जिसे उन्होंने राज्य के लिए चिंता का विषय बताया। उन्होंने आगे कहा कि घर-घर केसीसी अभियान के दौरान प्रयासों के परिणामस्वरूप अक्टूबर 2023 से दिसंबर 2023 तक 8.13 लाख किसानों को केसीसी जारी किया गया है, जो एक उत्साहजनक आंकड़ा है, हालांकि उन्होने कहा कि हमने अभी भी राज्य के सभी किसानों को कवर नहीं किया है जिसे ध्यान में रखते हुए वित्त वर्ष 2024-25 के लिए crop loan के तहत अनुमान 8024 करोड़ रुपये रखा गया है।

(एक्शन- सभी सदस्य के जानकारी हेतु)

❖ श्री जहागीरदार ने सभा को बताया कि विगत वर्ष में पशुपालन व मत्स्य पालन में सिर्फ 38 करोड़ रुपय का ऋण वितरण हुआ है जिससे 4,900 लोग ही लाभान्वित हुए हैं। उन्होने सभा सदस्यों को बताया कि आज की तारीख में cage fishing कर रहे किसानों की औसत मासिक आय दो लाख रुपय से भी अधिक पहुँच गई है जो की बैंकर्स के लिए एक सकारात्मक संकेत है, उन्होने बैंकों से इस श्रेणी में अधिक से अधिक ऋण वितरण करने का आग्रह किया।

उन्होने नाबार्ड द्वारा बैंकर्स के लिए exposure visit करवाने का प्रस्ताव रखा और बताया कि हाल ही में नाबार्ड द्वारा बैंकेर्स के लिए एक exposure visit कारवाई गयी थी।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड ने सभा सदस्यों को बताया कि वित्तीय वर्ष 23-24 की दिसंबर तिमाही तक एग्रिकल्चर टर्म लोन के लिए तय 7,945 करोड़ रुपय के लक्ष्य के विरुद्ध 5,425 करोड़ रुपय का ऋण वितरण हुआ है, जो की लक्ष्य का 68% है।

उन्होने आगे यह भी बताया कि राज्य में दुग्ध उत्पादन कम है और झारखण्ड में इसकी आपूर्ति मुख्यतः बिहार की सुधा डेयरी से होती है। उन्होने बताया कि नाबार्ड ने RIDF के अंतर्गत चार नए डेयरी प्लांट्स की स्थापना के लिए लगभग 255 करोड़ रुपय का ऋण प्रदान किया है, इस कदम से दुग्ध उत्पादन समितियों का गठन बढ़ेगा और उनके लिए मार्केट की उप्लभ्धता भी बढ़ेगी। उन्होने बैंकर्स से इसे अवसर स्वरूप लेते हुए अधिक से अधिक ऋण डेयरी के लिए देने को कहा।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्री जहागीरदार ने सभा सदस्यों को बताया कि विगत वर्ष 2023-24 में कृषि क्षेत्र के लिए PLP 14630 करोड़ था वहीं इस क्षेत्र में एस.एल.बी.सी द्वारा 17086 करोड़ रुपय का ACP लक्ष्य रखा गया था , इस लक्ष्य के विरुद्ध दिसंबर तिमाही तक राज्य के बैंकों ने कुल 10165 करोड़ रुपय का ऋण वितरण किया, जो की लक्ष्य का लगभग 60% रहा।

इसे देखते हुए नाबार्ड के स्टेट फोकस पेपर में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कृषी क्षेत्र के लिए 18734 करोड़ की क्षमता का आंकलन किया गया है जो की विगत वर्ष से 28% ज़्यादा है।

(एक्शन- सभी सदस्यों के जानकारी हेतु)

❖ नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने कहा कि निर्यात ऋण उन क्षेत्रों में से एक है जहां झारखंड राज्य पिछड़ रहा है। उन्होंने कहा कि नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 50.00 करोड़ रुपये का अनुमान रखा था, किन्तु बैंकों ने इस श्रेणी के तहत किसी भी लाभार्थी को कोई धनराशि वितरित नहीं की है।

श्री जहागीरदार ने आगे कहा कि झारखंड राज्य में फलों एवं सब्जियों के निर्यात की अपार संभावना है क्यूंकि झारखंड देश का एकमात्र राज्य है जहां फूलगोभी और पत्तागोभी साल भर उगते हैं, इसलिए ऐसा माना जाता है कि यहां फलों और सब्जियों के निर्यात की सम्पूर्ण समभावनाए हैं।

श्री जहागीरदार ने सदन को बताया कि झारखंड में किसान स्ट्रॉबेरी, ड्रैगन फ्रूट, अंजीर और कई अन्य विदेशी फल उगा रहे हैं, जिस कारण नाबार्ड ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए निर्यात ऋण के लिए 230 करोड़ रुपये की संभावना का अनुमान लगाया है। उन्होंने राज्य सरकार से रांची हवाई अड्डे और अन्य स्थानों पर पैक हाउस, ग्रेडिंग यूनिट, कार्गो हैंडलिंग, बंदरगाह और अन्य बुनियादी ढांचे की स्थापना पर विचार करने का अनुरोध किया ताकि निर्यातकों को कृषि उपज के निर्यात के लिए अपने लाइसेंस और प्रमाण पत्र मिल सकें।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं राज्य सरकार)

- नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक ने बताया कि PMFME और AIF के तहत बहुत बड़ी संख्या में प्रस्तावों को मंजूरी नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि इसका मुख्य कारण यह है कि उधारकर्ता वह सुरक्षा प्रदान करने में असमर्थ हैं जिसकी बैंकरों को आवश्यकता होती है क्योंकि इन ऋणों के लिए भूमि को बंधक करने कि आवश्यकता होती है जिस पर plant और machinery स्थापित की जाती हैं। उन्होंने आगे कहा कि सीएनटी/एसपीटी अधिनियम के प्रावधान और इन उधारकर्ताओं की सांस्कृतिक अनिच्छा के कारण उद्यमियों को भूमि बंधक प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

  उन्होंने आगे कहा कि एस॰एम॰ई क्षेत्र के माध्यम से वित्तपोषण को आसान बनाने और विशेष रूप से PMFME क्षेत्र में ऋण के अच्छे प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के लिए, श्री जहागीरदार ने एस॰एल॰बी॰सी से झारखंड राज्य में PMFME, AIF के तहत वित्तपोषित इकाइयों के लिए विशेष रियायत प्रदान करने के लिए आरबीआई और भारत सरकार के साथ मामला उठाने का अनुरोध किया ताकि इन ऋणों के लिए बंधक की शर्त को माफ किया जा सके। उन्होंने आगे कहा कि इन इकाइयों की सीमा अधिकतम 5-10 लाख हो सकती है ताकि PMFME के तहत वित्त पोषित अधिकांश इकाइयों को मंजूरी दी जा सके।

(एक्शन- एस॰एल॰बी॰सी एवं भारतीय रिजर्व बैंक)

- श्री जहागीरदार ने बताया कि वित्त वर्ष 2023-24 के लिए SHG के तहत राज्य फोकस अनुमान Rs.2348 करोड़ और ACP लक्ष्य के अनुसार Rs.2718 करोड़ रखा गया था किन्तु इस लक्ष्य के मुक़ाबले दिसंबर 2023 तक बैंकों ने लक्ष्य का 50% से भी कम हासिल किया है। उन्होंने बैंकरों से SHG को वित्त्यपोषित करने का अनुरोध किया क्योंकि इस क्षेत्र के तहत एनपीए प्रतिशत भी न्यूनतम है। उन्होंने आगे कहा कि नाबार्ड ने इस क्षेत्र के तहत वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 2480 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- श्री जहागीरदार ने नाबार्ड द्वारा की जा रही विभिन्न पहलों पर भी प्रकाश डाला, जैसे RIDF के तहत डेयरी प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए समर्थन, पैक्स/लैंप्स का कम्प्यूटरीकरण, 3 उत्पादों की जी॰आई टैगिंग, कृषि और गैर-कृषि उत्पादों की बिक्री के लिए प्रदर्शनियों का आयोजन।

(एक्शन- सभी सदस्यों के जानकारी हेतु)

- श्री जहागीरदार ने यह भी सुझाव दिया कि, राज्य सरकार को अंजीर की खेती, स्वदेशी नस्लों के साथ गर्भाधान द्वारा गैर-वर्णनात्मक मवेशियों की नस्ल सुधार जैसे थारपारकर , गिर, लाल सिंधी के तहत ऋण बढ़ाने के लिए एक समग्र योजना तैयार करनी चाहिए। इस योजना में ग्रामीण साहसिक पर्यटन, जलाशयों में तैरते सौर पैनल,

रांची हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क निकासी पोस्ट की स्थापना, ग्रामीण औद्योगिक संपदा की स्थापना आदि भी शामिल करने की सलाह भी श्री जहांगीरदार ने दी।

(एक्शन- राज्य सरकार)

- ❖ उन्होंने तसर के उत्पादन को सुविधाजनक बनाने के लिए रोग मुक्त लेईंग इकाइयों, भंडारण, नीलामी घरों आदि की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि हाउसिंग सोसाइटियों/कॉलोनियों और प्रमुख बाजारों में मेधा डेयरी स्टाइल कियोस्क की स्थापना करनी चाहिये जिनके माध्यम से S.H.G महिलायँ अपने उत्पाद बेच सकें।

(एक्शन- राज्य सरकार, JSLPS, नाबार्ड)

- ❖ श्री जहागीरदार ने आगे उल्लेख किया कि राज्य में मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी आदि के विभिन्न नोड्स में वित्त पोषण के पर्याप्त अवसर हैं, जिससे ऋण जमा अनुपात में सुधार हो सकता है।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक)

- ❖ श्री जहागीरदार ने कहा कि राज्य में बांस की खेती अच्छी मात्र में होती है, इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह तथा और भी कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होने यह भी बताया की इस बावत नाबार्ड द्वारा एक conclave भी किया जाएगा, जिसमे बैंको व झारखंड चैंबर ऑफ कॉमर्स की सहभागिता अपेक्षित रहेगी।

(एक्शन- सभी सदस्यों के जानकारी हेतु)

- ❖ श्री जहागीरदार ने अंत में आने वाली एस॰एल॰बी॰सी त्रैमासिक बैठकों की संरचना में संशोधन का आग्रह किया, जिसमें उन्होने सभा में मौजूद बैंकों के अन्य वरिष्ठ अधिकारी गणों को भी विचार साझा करने का मौका देने की बात कही। उन्होने बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों से भी आग्रह किया कि वर्ष में कम से कम एक या दो बार एस॰एल॰बी॰सी उप-समितियों की बैठक में अपनी सदस्यता सुनिश्चित करें जिससे सूक्ष्म मुद्दों के बारे में भी उन्हे जानकारी रहे।

(एक्शन- एस॰एल॰बी॰सी एवं समस्त बैंक)

अपने भाषण के समापन में मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड ने राज्य सरकार व बैंकों से एकजुट होकर स्टेट फोकस के अनुमानित निर्धारनों को यथार्थ में बदलने का आह्वान किया।

ग़) भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह का सम्बोधन

- ❖ भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक, श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह ने 86वीं एसएलबीसी बैठक में सभी हितधारकों का स्वागत किया और कहा कि यह त्रैमासिक बैठक **विशेष एसएलबीसी बैठक है।** उन्होने यह भी कहा कि इस बैठक को वो एक परस्पर संवादात्मक बैठक के रूप में आगे ले जाना चाहेंगे।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- ❖ श्री सिंह ने सभी हितधारकों से कहा कि चूंकि झारखंड एक संभावनाओं से परिपूर्ण प्रदेश है, राज्य सरकार के vision document को मद्देनज़र रखते हुए एक ठोस कार्ययोजना बनाई जानी चाहिए जिससे न केवल राज्य, राष्ट्रीय औसत को प्राप्त कर सकें बल्कि उसे पार भी कर सकें।

(एक्शन- एस॰एल॰बी॰सी, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड एवं राज्य सरकार)

- ❖ सभा सदस्यों से श्री सिंह ने यह कहा कि वित्तीय साक्षारता व वित्तीय समावेशन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक कटिबद्ध है। इसी क्रम में 31-03-2024 तक सभी बैंक खातों का digitisation, वित्तीय साक्षारता एवं

जागरूकता फैलाने के लिए 26-02-2024 से शुरू हो रहे वित्तीय साक्षारता सप्ताह का आयोजन, राज्य में भारतीय रिजर्व बैंक के कुछ अहम कदम हैं।

वित्तीय साक्षारता सप्ताह के बारे में आगे बात करते हुए उन्होने यह बताया कि 4 मार्च से 10 मार्च तक digital awareness week के रूप में मनाया जा रहा है जिसमें डिजिटल उत्पादों का सुरक्षित उपयोग के बारे में जागरूकता फैलाई जाएगी।उन्होने यह भी बताया की इस क्रम में राज्य के नौजवानों पर मुख्यतः ध्यान केन्द्रित करते हुए और उन्हे साइबर धोखाधड़ी के प्रति जागरुक करते हुए, निबंध आदि प्रतियोगिताएं भी चलायी जा रही हैं।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- श्री सिंह ने सभा सदस्यों को RBI Innovation Hub एवं Fintech विभाग के बारे में बताया। उन्होने आगे यह भी बताया कि जिन राज्यों में भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण हो चुका है ,भारतीय रिजर्व बैंक के- RBI Innovation Hub एवं Fintech विभाग के प्रयास से उन राज्यों में किसानों को कुछ ही मिनटों में ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है- जैसे तमिल नाडु , मध्य प्रदेश। **उन्होने राज्य सरकार से झारखंड में भी जल्द से जल्द भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण एवं Online Charge Creation की सुविधा का आग्रह किया।** उन्होने सभा को यह भी बताया कि Dairy क्षेत्र के कृषकों के अभिलेखों का डिजिटलीकरण अमूल व मेधा जैसी कंपनियों द्वारा किया जा चुका है।

(एक्शन- राज्य सरकार)

सभी हितधारकों के परस्पर सहयोग से राज्य की प्रगती की कामना के साथ श्री सिंह ने अपनी वाणी को विराम दिया।

घ) सचिव, वित्त विभाग, - झारखंड सरकार श्री प्रशांत कुमार का सम्बोधन

- सचिव -वित्त विभाग ने अपने प्रारम्भिक वक्तव्य में सभा में उपस्थित सभी गणमान्यों का अभिनंदन किया एवं राज्य के ऋण जमा अनुपात में बढ़ोतरी के लिए बैंकों को बधाई देते हुए कहा कि ऋण जमा अनुपात में वृद्धि ,निश्चय ही हर्ष का विषय बताया। उन्होने आगे यह भी कहा की राज्य अभी भी राष्ट्रीय औसत से बहुत दूर हैं और सभी हितधारकों को इस ओर कार्य करने की आवश्यकता है।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक)

- श्री प्रशांत कुमार ने सभा को बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं आजीविका के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं। उन्होने यह भी कहा कि इसमें बैंक अच्छा कार्य कर रहे हैं किन्तु उनसे और सहयोग अपेक्षित है, इस क्रम में उन्होने यह भी बताय कि बैंकों के पास अभी भी स्वयं सहायता समूहों के करीब 6000 आवेदन लंबित हैं तथा उन्होने सभी बैंक प्रमुखों से ग्रामीण विकास विभाग की ओर से आग्रह किया कि वे यथाशीघ्र इनका निष्पादन करवाएँ।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक)

- सचिव महोदय ने बताया कि पूर्व में वे ग्रामीण विकास विभाग के कार्यभार में थे और उस समय सभी बैंकों से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बैंक BC के रूप में नियुक्त करने की मुहिम चलायी गयी थी। इस संदर्भ में उन्होने आशा जताई कि समस्त बैंक इस क्षेत्र में प्रगति कर रहे होंगे।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ सचिव महोदय ने सभा को इस बात से अवगत कराया कि झारखंड सरकार का जल संसाधन विभाग नयी तकनीक के सहयोग से 4 मेगा ड्रिफ्ट परियोजनाएं लाया है, जिनमें pipeline के माध्यम से लगभग 62000 हेक्टेयर भूमि की सिंचाई हो सकेगी उन्होने यह भी बताया कि इन परियोजनाओं को पूर्ण होने में दो से तीन वर्षों का समय लगेगा। इस संदर्भ में उन्होने नाबार्ड द्वारा आच्छादित गीरिडीह ज़िले में स्थित सोन कंहर परियोजना एवं दुमका ज़िले के मसलिया योजना का ज़िक्र किया। उन्होने कहा कि वे आशा करते हैं कि इन सभी परियोजनाओं से कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह की संभावनाएँ बढ़ेंगी।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

❖ वित्तीय समावेशन के बारे में बात करते हुए सचिव महोदय ने कहा कि आज की तारीख में डिजिटल मंचों की उपलब्धता के कारण हर किसी को बैंकिंग सुविधा दे पाना संभव हो गया है साथ ही साथ उन्होने यह भी कहा कि डिजिटल मंचों के होने के बावजूद भी ब्रिक अँड मोर्टर ब्रांचों की अपनी महत्ता है।

इस क्रम में आगे उन्होने सभा कि बताया कि राज्य के बैंकों ने 38 में से 35 बैंकरहित गावों में ब्रिक व मोर्टर ब्रांच खोल दी हैं।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

❖ उन्होने आगे वृद्धावस्था पेंशन योजना , सावित्री बाई फुले जैसी स्कीम का उल्लेख करते हुए कहा कि ऐसी सरकारी योजना के लाभूकों कि संख्या में कई गुना बढ़ोतरी हुई है तथा योजनाओं का पैसा लाभुक तक DBT के माध्यम से पहुंचाने के लिए उनका बैंक खाता होना आवश्यक है जिसमे बैंकों की भूमिका अहम है। इस क्रम में उन्होने सभी बैंकों से लाभुकों का खाता खोलने का आग्रह किया और digital payments उत्पादों विशेषकर UPI का भी उल्लेख किया।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक)

❖ सचिव महोदय ने सभा सदस्यों को यह बताया की वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट की सबसे अहम और बड़ी राज्य योजना के रूप में **अबूआ आवास योजना** आ रही है जिससे राज्य के ग्रामीण इलाकों का समेकित विकास होगा। प्रधान सचिव महोदय ने बैंकों से इसे अवसर के रूप में लेने को कहा।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक)

❖ सचिव महोदय ने मुख्य सचिव कार्यालय से आए एक प्रेक्षण का उल्लेख किया जिसमें SC/ST छात्रों को शिक्षा ऋण में कमी की बात कही गयी थी। उन्होने कहा कि राज्य ने शिक्षा ऋण में अच्छा प्रदर्शन किया है किन्तु इसमे इस विशेष वर्ग की हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्री कुमार ने अपने वक्तव्य में बताया की सरकारी विभागों में दी जानेवाली बैंक गैरंटी में फ्रॉड की घटनाओं में वृद्धि हुई हैं और बैंकों को इससे बचने के लिए e- बैंक गारंटी को जल्द से जल्द कार्यान्वित करना चाहिए उन्होने यह भी बताया की सरकार का works department भी इस क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है ।

श्री कुमार ने बैंक गैरंटी से जुड़ी धोखाधड़ी की घटनाओं के निबटान के लिए राज्य के सभी बैंकों से e- बैंक गारंटी लागू करने का आग्रह किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ राज्य में frictionless credit हो सके ,इसके लिए क्षेत्रीय निदेशक रिजर्व बैंक श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह के भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण के सुझाव को, सचिव महोदय ने अनुकरणीय बताया। उन्होने यह भी कहा कि झारखंड सरकार इसके क्रियानवन के लिए एक **उच्च स्तरीय समिति** बनाने के बारे में विचार कर रही है , जिसमें

राजस्व विभाग, कृषि विभाग,वित्त विभाग समेत कई अन्य विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। प्रधान सचिव महोदय ने एस॰एल॰बी॰सी से इस बावत पत्राचार करने का भी आग्रह किया।

इस संदर्भ में उन्होने **परिमार्जन पोर्टल** का भी ज़िक्र किया जिसमें झारखंड के जिन भूमि अभिलेखों का डिजिटलीकरण हो चुका है, उनका शुद्धिकरण किया जा रहा है।

(एक्शन- एस॰एल॰बी॰सी)

ङ) कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ इंडिया, श्री एम. कार्तिकेयन का सम्बोधन

कार्यपालक निदेशक, श्री एम. कार्तिकेयन ने 86वीं एस.एल.बी.सी सभा में सम्मिलित सभी सदस्यों का अभिवादन किया। उन्होने विशेषकर, श्री प्रशांत कुमार को सचिव, वित्त विभाग के रूप में उनकी पहली एस.एल.बी.सी में सम्मिलित होने के लिए अभिवादन किया।

- ❖ श्री कार्तिकेयन ने सचिव, वित्त विभाग के सहायता समूहों के वित्तपोषन के सुझाव को अनुकरणीय बताया। उन्होने पूर्व वक्ताओं के भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण एवं online charge creation के सुझाव से भी श्री कार्तिकेयन ने सहमति जताई।

(एक्शन- सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- ❖ श्री कार्तिकेयन ने आजीविका मिशन में बैंकों का योगदान बढ़ाने के लिए सचिव महोदय के सुझाव का समर्थन किया। उन्होने सभी बैंकों से आग्रह किया कि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों के बचत खाते खोले जाएँ जिससे छात्रवृति DBT के माध्यम से उन तक पहुँच सके।

  उन्होने यह भी कहा कि झारखंड के 24 जिलों में से19 महत्वाकांक्षी ज़िले हैं और इनकी प्रगति के लिए यह आवश्यकता है की यहाँ के SC, ST छात्रों को शिक्षा ऋण ज़रूर उपलब्ध कराया जाय।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- ❖ श्री कार्तिकेयन ने सचिव महोदय की e-बैंक गारंटी की बात का समर्थन करते हुए सभी बैंकों से इसमे कार्य करने की अपील करी और सभा को यह भी बताया की बैंक ऑफ इंडिया भी एक बड़ी कंपनी के साथ मिलकर इस क्रम में आगे बढ़ रही है।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- ❖ श्री कार्तिकेयन ने सभा सदस्यों को अवगत कराया कि राज्य में कुल जमा राशी 3.25 लाख करोड़ जिसके विपरीत बैंकों ने मात्र 1.5 लाख करोड़ का ऋण वितरण किया है। उन्होने ने कहा की यह एक चिंतनीय विषय है। उन्होने NABARD को PLP लाने के लिए धन्यवाद दिया और सभी हितधारकों विशेषकर अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से आग्रह किया कि वे इसे यथार्थ में बदलें

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक)

- ❖ श्री कार्तिकेयन ने राज्य के सभी बैंकों के ब्रांच शाखावार वित्तपोषन के आंकड़े पर प्रकाश डालते हुए यह बताया कि, झारखंड राज्य में SBI का प्रति शाखा ऋण वितरण 63.00 करोड़ रूपय है, वहीं JRGB का प्रति शाखा ऋण वितरण 13.00 करोड़ रूपय है, यह आंकड़ा बैंक ऑफ बड़ोडा के लिए 35.00 करोड़ रूपय है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए 36.00 करोड़ रूपय है, कनारा बैंक के लिए 39.00 करोड़ रूपय है। उन्होने निजी क्षेत्र के बैंकों की सराहना करते हुए यह कहा की यह आंकड़ा HDFC बैंक के लिए 132 करोड़ रूपय है, ICICI के लिए 112 करोड़ रूपय है वहीं AXIS बैंक के लिए 63 करोड़ रूपय है, वहीं BOI के लिए यह आंकड़ा 49 करोड़ रूपय है, उन्होने सभी अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों एवं बैंकों से उचित दिशा में और तीव्र गती से कार्य करने का अनुरोध किया

(एक्शन- समस्त सार्वजनिक बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक)

❖ श्री कार्तिकेयन ने अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों की समीक्षा करते हुए कहा कि गुमला में CASA जमा राशी में खराब प्रदर्शन है तथा गढ़वा ज़िले में सुरक्षा बीमा योजना में खराब प्रदर्शन है। वहीं बोकरो, चतरा, देवघर, धनबाद, दुमका, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, हजारीबाग, जामतारा, कोडरमा, हाजरीबाग, खूंटी, पलामू , सिमडेगा, रांची, सिमडेगा, पश्चिमी सिंघभूम जिलों में ऋण जमा अनुपात में सुधार की आवश्यकता है इन सभी अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों से कहा गया कि अगली SLBC बैठक तक इन पैमानों में सुधार सुनिश्चित करें ।

(एक्शन- उपरोक्त ज़िलों के अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

❖ श्री कार्तिकेयन ने सभा को यह बताया राज्य ने शिक्षा ऋण, SC, ST समुदाय को ऋण में वृद्धि दर्ज की गयी है किन्तु **PM Svanidhi में और कार्य करने की आवश्यकता है ।**

(एक्शन- समस्त बैंक)

❖ श्री कार्तिकेयन ने सभी अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों का ध्यान RSETIs की ओर आकर्षित किया, उन्होने credit linkage पर विशेष ध्यान देने की अपील करी और उसको 100% तक बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होने यह भी कहा कि RSETI में ट्रेनिंग प्रतिशत में भी उत्साहजनक नहीं है, उन्होने सभी RSETI निदेशक और अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों को इसमे सुधार सुनिश्चित करने को कहा।

उन्होने RSETIs की बिल्डिंग निर्माण हेतु, ज़रूरत पड़ने पर भूमि आवंटन में राज्य सरकार से सहायता की अपील की।

(एक्शन- समस्त अग्रणी ज़िला प्रबन्धक एवं RSETI निदेशक)

❖ श्री कार्तिकेयन ने सभा सदस्यों को यह बताया कि किसानों को जागरूक करने कि आवश्यकता है कि वे अपने KCC ऋण को ससमय चुकाएँ, जिससे बैंक उन्हे 24 घंटों के अंदर नए Scale of Finance के आधार पर पुनः ऋण दे सकें।

उन्होने यह भी बताया कि बैंक रेडियो, AUTO जैसे कई तरीकों से इसका प्रचार कर रहे हैं, किन्तु बहुत संतोष-जनक परिणाम सामने नहीं आये हैं, इस कार्य में राज्य सरकार कि सहायता कि अपील उन्होने करी।

(एक्शन- राज्य सरकार)

❖ उन्होने सभी बैंकों से आग्रह किया कि डिजिटल बैंकिंग उत्पादों से अपने सभी स्टाफ सदस्यों को पूर्णतः अवगत कराएं, जिससे उनके माध्यम से जनमानस इन सभी उत्पादों को पहुंचाया जा सके व इनसे संबन्धित सावधानियों के बारे में भी वे जागरूकता फैला सकें।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक)

❖ उन्होने सभी बैंकों से यह भी आग्रह किया कि MSME borrowers के बीच भी financial discipline व विभिन्न ratios को लेकर जानकारी फैलाने की आवश्यकता है ताकी छोटे-छोटे कारणों से उनके ऋण आवेदन अस्वीकरत न हों।

(एक्शन- समस्त बैंक एवं अग्रणी जिला प्रबंधक)

❖ उन्होने सभी वरिष्ठ बैंकर्स से उनके चुनिन्दा शाखा प्रबन्धको के साथ मत्स्य पालन की विभिन्न परियाजनों को दौरा करने के लिए कहा जिससे इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह की संभावनों से वे परिचित हो सकें और फलस्वरूप इसमें वृद्धी हो।

(एक्शन- समस्त बैंक)

श्री कार्तिकेयन ने अन्य वक्ताओं के विभिन्न सुझाओं जैसे Bamboo Farming, Food Processing, Floating Solar Panels, Rural Adventure Tourism पर अमल करने के आश्वासन के साथ अपनी वाणी को विराम दिया।

व्यवसायिक सत्र

व्यावसायिक सत्र का संचालन वरिष्ठ प्रबन्धक ,राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, श्री रोशन चौधरी द्वारा किया गया, इस सत्र में श्री चौधरी ने सभा अध्यक्ष श्री कार्तिकेयन व क्षेत्रीय निदेशक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की सहभागिता के साथ सभी बैंक व अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों की समीक्षा करी।

- श्री चौधरी ने सभा को बताया कि राज्य के ऋण जमा अनुपात में 4.12% कि वर्ष दर वर्ष वृद्धि दर्ज हुई है, वहीं जमा राशि में यह वृद्धि 11.82 % है एवं ऋण में यह वृद्धी 16.42% रही। वहीं NPA में 16.99% की कमी दर्ज हुई है।

  (एक्शन- सभी सदस्यों के जानकारी हेतु)

- श्री चौधरी ने बताया की दिसम्बर तिमाही की सभी एस॰एल॰बी॰सी-उपसमितियों की बैठक हो चुकी हैं, किन्तु किसी कारण वश SHG-RSETI उपसमिति की बैठक अब तक नहीं हो पायी है जो कि संबंधित विभाग द्वारा जल्द ही करवा ली जाएगी।

  सभाध्यक्ष ने सभी अग्रणी ज़िला प्रबन्धकों को ससमय सभी BLBC/DCC/DLRC बैठकों को ससमय करने की हिदायत दी।

  (एक्शन- ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड सरकार एवं सभी अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

- विभिन्न उपसमितियों में कि गयी परिचर्चा कि मुख्य बिन्दुओं से सभा को अवगत करवाते हुए श्री चौधरी ने बताया कि सर्टिफिकेट केस की फीस में कटौती का आग्रह राज्य सरकार से किया गया है। एटीएम मशीन में GPS चिप्स लगाने/GEOTAGGING का सुझाव भी बैंकों को दिया गया।

  उन्होने ने 38 में से 36 चिन्नहित स्थानों पर बैंकों द्वारा शाखा खोले जाने की बात बतायी। सभाध्यक्ष महोदय के पूछे जाने पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बताया की ज़िला पदाधिकारी –BDO के स्तर से करार करने में विलंब हो रही है, किन्तु बैंक MICR कोड समेत अन्य कार्य किए जा चूकें है। वहीं यूको बैंक ने बताया कि फ़रवरी के अंत तक शाखा खोलने का आश्वासन सभा को दिया गया।

  (एक्शन- राज्य सरकार, बैंक ऑफ महराष्ट्र, यूको बैंक)

- राज्य में बैंक, बी॰सी व एटीएम नेटवर्क के बारे में जानकारी देते हुए श्री चौधरी ने कहा, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, दुमका, गुमला, रांची, सरायकेला खरसावां, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद, दुमका जिलों में BC per lakh population की संख्या राज्य के औसत से कम है, वहीं चतरा, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, लातेहार, पाकुड़, पलामू, साहेबगंज, सिमडेगा ज़िले में Branch per lakh population की संख्या राज्य के औसत से कम है तथा चतरा, दुमका, गढ़वा, गिरिडीह, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, कोडरमा, लातेहार, पाकुड़, पलामू, साहेबगंज, सिमडेगा जिलों में ATM per lakh population की संख्या राज्य के औसत से कम है।

  (एक्शन- उपरोक्त सभी अग्रणी ज़िला प्रबन्धक)

- क्षेत्रीय निदेशक रिजर्व बैंक ने सबसे ज़्यादा INACTIVE BCs रखने वाले बैंकों से स्पष्टीकरण मांगा, इस क्रम में सर्वप्रथम YES बैंक के प्रतिनिधि ने यह बताया कि वे इस ओर कार्य कर कर रहे हैं। क्षेत्रीय निदेशक रिजर्व बैंक ने कहा कि आम जनता को निरबाध्य सेवा देने के लिए व धोखाधड़ी से बचाने के लिए INACTIVE BCs को ACTIVE में बदलना आवश्यक है।

  Fino Payments Bank ने बताया कि वे लगभग 4000 ऐसे BCs को जल्द ही रिप्लेस कर रहे हैं जो निष्क्रिय हैं। इसी के साथ SHG मेम्बर्स को BC नियुक्त करने के लिए भी कहा गया।

(एक्शन- येस बैंक, फिनो पेमेंट बैंक)

- क्षेत्रीय निदेशक रिजर्व बैंक ने आगे कि बैठकों में राष्ट्रीय औसत का उल्लेख करने के सलाह दी जिससे सही मायने में अपने राज्य के प्रदर्शन का आंकलन हो सके।

(एक्शन – एस॰एल॰बी॰सी)

- श्री चौधरी ने जनसुरसक्षा योजनाओं के आंकड़े प्रस्तुत करते हुए यह बताया कि राज्य में PMJJBY और PMSBY में गिरावट आयी है, जिसका कारण मुख्यतः SBI के आंकड़ों में गिरावट पायी गयी, SBI के प्रतिनिधि ने इसका स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि क्यूंकी अब उनका बैंक सिर्फ जीवित policies की ही गढ़ना कर रही है इस लिए बैंक में यह गिरावट दर्ज कि गयी है, किन्तु अब उनके आंकड़े संतुलित हो चुके हैं ।

(एक्शन – सभी सदस्यों की जानकारी हेतु)

- राज्य के ऋण जमा की समीक्षा के दौरान सभाध्यक्ष ने पश्चिमी सिंघभूम को कम ऋण जमा अनुपात के कारण का विश्लेषण कर सुधार करने की सलाह सभाध्यक्ष महोदय ने दी।

(एक्शन – एलडीएम पश्चिमी सिंघभूम)

- श्री चौधरी ने सभी बैंकों से आग्रह किया कि यदि उनकी शाखाओं को किसी प्रकार की अवसंरचनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा हो तो उसकी जानकारी एस॰एल॰बी॰सी को उपलब्ध कराएं, जिससे राज्य सरकार से इस बावत सहायता ली जा सके। श्री चौधरी ने बताया की यह रिपोर्ट सभी बैंकों से मांगी गयी थी किन्तु यूको बैंक के अलावा यह जानकारी किसी अन्य बैंक ने नहीं दी।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- सभी खातों के 100% डिजिटलीकरण अभियान पे चर्चा करते हुए क्षेत्रीय निदेशक रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों को 15 मार्च तक सभी खातों का डिजिटलीकरण करने के लिए निर्देशित किया।

(एक्शन- समस्त बैंक)

- राज्य के ऋण खातों के NPA होने की स्थिति की समीक्षा के दौरान श्री चौधरी ने सरकारी प्रायोजित योजनाओं में बढ़ रहे NPA को चिंताजनक बताया, इस क्रम में उन्होने यह बताया कि PMEGP में NPA 25.18% है, मुद्रा में यह आंकड़ा 10.85% है, वहीं Stand-Up India में यह आंकड़ा 4.64% है।

  आगे की चर्चा में सभाध्यक्ष श्री कार्तिकेयन ने Non-Priority Sector में बढ़ रहे NPA को चिंताजनक बताते हुए SLBC को निर्देश दिया कि यह आंकड़े बैंकों के साथ साझा कर दिये जाएँ जिससे आने वाली तिमाही तक बैंक इसकी रोकथाम कर सकें।

(एक्शन –एस॰एल॰बी॰सी एवं समस्त बैंक)

- क्षेत्रिय निदेशक रिजर्व बैंक ने DLRC बैठकों की आवृत्ति को घटाने का प्रस्ताव सभा के समक्ष रखा। उन्होने कहा कि इन बैठकों में जन प्रतिनिधि की उपस्थिती वांछनीय रहती है, किन्तु जन प्रतिनिधि हर बैठक में

सम्मिलित रहने में असमर्थ रहते हैं इसलिए यदि इन बैठकों को हर तिमाही में न करके अर्धवार्षिक तौर पर किया जाय तो अच्छा होगा। इस विषय आम सहमति न होने की दशा में कोई ठोस निर्णय सभा में नहीं हो पाया।

(एक्शन – एस॰एल॰बी॰सी एवं भारतीय रिजर्व बैंक)

❖ **व्यावसायिक सत्र के अंत में उठाए गए कुछ मुद्दे –**

क) विशेष सचिव कृषि विभाग, श्री प्रदीप हज़ारी ने SLBC से KCC के सम्पूर्ण डाटा का आग्रह किया जिसमें सभी नये, सक्रिय एवं NPA खातों का विवरण हो।

(एक्शन – एस॰एल॰बी॰सी)

ख) State Director RSETI श्री शशी भूषण मिश्रा ने सभा को बताया की **नये RSETI के capital expenditure** के लिए ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार ने 1 करोड़ की राशि को बढ़ा कर 2 करोड़ कर दिया है किन्तु यह सुविधा पहले से मौजूद RSETIs के लिए नहीं है। उन्होने नाबार्ड एवं राज्य सरकार से संदर्भ में सहायता का आग्रह किया।

(एक्शन – राज्य सरकार एवं नाबार्ड)

ग) झारखंड स्माल इंडस्ट्रीज़ असोसिएशन (J.S.I.A) से आए श्री शिवम सिंह ने उन बैंकों के नाम देने का आग्रह किया जो की **e- Bank Guarantee** दे रहे हैं। राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की ओर से उसे जल्द ही उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।

(एक्शन – एस॰एल॰बी॰सी)

व्यावसायिक सत्र के समापन के बाद महाप्रबंधक नाबार्ड श्री गौतम कुमार सिंह ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए प्रारूपित State- Focus पर powerpoint प्रस्तुतीकरण दिया।

बैठक के अंत में, एसएलबीसी के उप महाप्रबंधक श्री अनिल जगदीश जाधव जी ने एस.एल.बी.सी की 86वीं बैठक में शामिल सदस्यों के लिए धन्यवाद ज्ञापन किया। सभा का संचालन श्रीमती प्राची मिश्रा,प्रबन्धक, रा. स्त. बै. स द्वारा किया गया।

(मनोज कुमार)
महाप्रबंधक, रा. स्त. बै. स.

86 वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति बैठक ,झारखंड				
15 फ़रवरी 2024 प्रोजेक्ट भवन ,धुर्वा, रांची□				
क्रमांक	नाम	पद	विभाग	संपर्क
1	श्री प्रशांत कुमार,भा०प्र०से	सचिव	वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार	
2	श्री एम कार्तिकेयन	कार्यपालक निदेशक	बैंक ऑफ इंडिया	
3	श्री प्रेम रंजन प्रसाद सिंह	क्षेत्रीय निदेशक	भारतीय रिजर्व बैंक	
4	श्री सुनील कृष्णा जहागीरदार	मुख्य महाप्रबंधक	नाबार्ड	
5	श्री मनोज कुमार	महाप्रबंधक	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	
6	श्री गौतम सिंह	महाप्रबंधक	नाबार्ड	
7	श्री □मीम अंसारी	उप महाप्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	9594566270
8	श्री अनिल जगदीश जाधव	उप महाप्रबंधक	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	9011060913
9	श्री अल्फ्रेड जी तिर्की	सहायक महाप्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	8902390446
10	श्री सोहम कुमार शोम□	प्रबंधक	भारतीय रिजर्व बैंक	8584895351
11	श्री सुमन एस साहू	उप महाप्रबंधक	नाबार्ड	9438125625
12	श्रीमती प्रीति आर थॉमस	उप महाप्रबंधक	नाबार्ड	
13	श्रीमती शोभा रानी के	सहायक महाप्रबंधक	नाबार्ड	
14	श्री गीतेश नायक	सहायक प्रबंधक	नाबार्ड	8587829222
15	श्रीमती शिवानी रोशन	सहायक प्रबंधक	नाबार्ड	9987288942
16	श्रीमती जसमिका बासके	सहायक प्रबंधक	नाबार्ड	
17	श्री लक्ष्मण कुमार	सहायक प्रबंधक	नाबार्ड	7549957855
18	लेफ़्टिनेंट कमांडर रोहित कुमार	सहायक प्रबंधक, पी & एस ओ	नाबार्ड	7702061522
19	श्री मनोज कुमार	प्रबंधक	नाबार्ड	9555312503
20	श्री संजय नायक	डी ए	नाबार्ड	
21	श्री रवि शंकर	डी डी एम	नाबार्ड	9910543421
22	श्री आशुतोष प्रकाश	डी डी एम	नाबार्ड	8609505580
23	श्री आकाश टोप्पो	प्रोजेक्ट एक्सएक्युटिव	एनजीओ - एएसए	9110035933
24	श्री विजय कुमार मौर्य	महाप्रबंधक	भारत संचार निगम लिमिटेड	9431200178
25	श्री गौतम भास्कर	सहायक महाप्रबंधक	भारत संचार निगम लिमिटेड	9431708822
26	श्री विवेक कुमार	एस डी	भारत संचार निगम लिमिटेड	9431100928
27	श्री श्रीनाथ जोशी	महाप्रबंधक	केनरा बैंक	9334913525
28	श्रीमती सोनालिका□	उप महाप्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	8712993610
29	श्री देवेश मित्तल	उप महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	9971981001
30	श्री एफ आर बुखारी	उप महाप्रबंधक	इंडियन बैंक	9051658238
31	श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव	उप महाप्रबंधक	पंजाब नेशनल बैंक	9958999735
32	श्री सुबोध कुमार	उप महाप्रबंधक	पंजाब नेशनल बैंक	8600400484
33	श्री सुनील कुमार	उप महाप्रबंधक	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	9264291876
34	श्री मदन मोहन बरियार	चेयरमैन	झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक	9304118032
35	श्री प्रवीण केरकेटा	पीएमयू	स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग	9199057058
36	श्री संजीव कुमार सिंह	उप महाप्रबंधक	बैंक ऑफ इंडिया	9769118862
37	श्री परिषेष पाठक	मुख्य कार्यकारी अधिकारी	झारखंड राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड	8709199091
38	श्री रमन श्रीवास्तव	सीटीओ	धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक	9798027478
39	श्री प्रदीप हजारी	विशेष सचिव सह सलाहकार	कृषि विभाग	9441821911
40	डॉ० अपर्णा कोपरपु	साइंटिस्ट-सी□	केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान	9302795569
41	श्रीमती पुनम रानी	एमआईएस मैनेजर	एसपीएमयू, पीएमएफएमई, उद्योग विभाग	7004964481
42	श्री शंभू प्रसाद यादव	उप निदेशक	मत्स्य पालन विभाग,झारखंड सरकार	7903097749
43	श्री विश्वजीत कुमार सिन्हा	सहायक महाप्रबंधक	भारतीय स्टेट बैंक	7718825815
44	श्री संजय कुमार	सहायक महाप्रबंधक	झारखण्ड राज्य ग्रामीण बैंक	8709316664

45	श्री शंकर महतो	सहायक महाप्रबंधक	बैंक ऑफ बड़ौदा	6287395610
46	श्री रोहित रमन	प्रबंधक	बैंक ऑफ महाराष्ट्र	8889810600
47	मेजर विक्रांत टंडन (सेवानिवृत्त)	आंचलिक प्रबंधक	यूको बैंक	9928635906
48	श्री बी चौधरी	सचिव□	सीसीडीएस	9771431432
49	श्री ए चौधरी□	सीईओ□	सीसीडीएस	9801685932
50	श्री शशि भूषण मिश्रा□	एसडीआर□	राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र,आरएसईटीआई	9330752100
51	श्री राजीव कुमार	सहायक निदेशक	केवीआईसी	9474059775
52	श्रीमती इंद्रा गुप्ता	संयुक्त सचिव	आईटी एवं ई-गवर्नेंस	898684646
53	श्री बिष्णु सी परिदा	मुख्य परिचालन अधिकारी	जेएसएलपीएस (आरडीपी जीओजे)	9939221549
54	श्री धीरज होरो	एसपीएम-एफ़आई	जेएसएलपीएस,आरडीडी	
55	श्री अनिल कुमार	एसएनओ-आरएसईटीआई	जेएसएलपीएस,	
56	श्री चंद्र भूषण पांडे	राज्य नियंत्रक	राष्ट्रीय अकादमी,रुडसेटी	9073396646
57	श्री मुकुल पी एक्का	सहायक महाप्रबंधक	सिडबी	7759811384
58	श्री पृथ्वीराज दास	सी एस ए	सिडबी	7002105955
59	श्री शिवम सिंह	माननीय सचिव	झारखंड लघु उद्योग संघ (जेएसआईए)	9835334399
60	श्री राजीव रंजन	वरिष्ठ प्रबंधक	इंडियन बैंक	8617763005
61	श्री प्रबोध कुमार `	वरिष्ठ प्रबंधक	केनरा बैंक	7520201560
62	श्री अनंत प्रसाद सिंह □	ए ई	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	9304406990
63	श्री बीपिन बिहारी□	मुख्य प्रबंधक	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	9490199015
64	श्री मनोज सिंह	सचिव□	साख फ़ाउंडेशन	9931128525
65	श्री सर्वेश कुमार	क्षेत्रीय प्रबंधक	इंडियन ओवरसीज बैंक	
66	श्री राजेन्द्र कुमार	मुख्य प्रबंधक	इंडियन ओवरसीज बैंक	9837130921
67	श्री रोहित कुमार	मुख्य प्रबंधक	पंजाब एंड सिंध बैंक	8437019190
68	श्री मनोज कुमार गुप्ता	उप महाप्रबंधक	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड	7781021133
69	श्रीमती अदिति घोष	क्षेत्र प्रमुख	आईडीएफसी फर्स्ट बैंक लिमिटेड	9835708422
70	**अनुपस्थित**		**फ़ेडरल बैंक लिमिटेड**	
71	श्री नवनीत गांधी	उप उपाध्यक्ष	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	9934011083
72	श्री मुकुल रेय	प्रबंधक	एचडीएफसी बैंक लिमिटेड	8804282048
73	श्री कौशल किशोर	क्षेत्र प्रमुख	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	9934313934
74	श्री शब्बीर अख्तर	क्षेत्र प्रमुख	आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड	9771499046
75	**अनुपस्थित**		**कर्नाटक बैंक लिमिटेड**	
76	श्री सुभास कुमार	राज्य प्रमुख	एक्सिस बैंक लिमिटेड	7260811600
77	श्री तुषार पट्टनक	राज्य प्रमुख	इंडसइंड बैंक	9937002677
78	श्री राज कुमार कमल	आरएच	इंडसइंड बैंक	9304143093
79	**अनुपस्थित**		**जम्मू एवं कश्मीर बैंक लिमिटेड**	
80	श्री आनंद कुमार□	क्लस्टर प्रमुख	यस बैंक	7873962227
81	श्री कमल चौधरी	वरिष्ठ प्रबंधक	कोटक महेंद्र बैंक लिमिटेड,	9386802023
82	श्री अरुण वी मोहन	प्रबंधक	साउथ इंडियन बैंक लिमिटेड	9048874928
83	श्रीमती ज्योति कुमारी	प्रबंधक	डीबीएस बैंक	7547088880
84	श्री शुभंम कुमार यादव	प्रबंधक	डीबीएस बैंक	9308202520
85	श्री वी विजय कुमार	प्रबंधक	करूर वैश्य बैंक	9505163878
86	श्री हिमांशु कुमार	राज्य प्रमुख	बंधन बैंक	7763803332
87	श्री राजेश	परिचालन प्रमुख	ईएसएएफ लघु वित्त बैंक लिमिटेड	9288013385
88	श्री रवि शंकर	वितरण प्रबंधक	उज्जीवन लघु वित्त बैंक	7781003289
89	**अनुपस्थित**		**उत्कर्ष लघु वित्त बैंक लिमिटेड**	
90	श्री प्रवीण कुमार ओझा	शाखा प्रबंधक	जना लघु वित्त बैंक	7004940734
91	श्री मुकेश कुमार मिश्रा	ए.वी.पी और शाखा प्रबंधक	ए यू लघु वित्त बैंक	9835474216

92	श्री विनायक पाटिल	ए.वी.पी	एयरटेल पेमेंट बैंक	9890999888
93	श्री अशोक कुमार पांडे	उपाध्यक्ष	फिनो पेमेंट बैंक	7566668649
94	श्री बिरज डेका	मुख्य प्रबंधक	इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक	9038224956
95	**अनुपस्थित**		**पेटीएम पेमेंट बैंक**	
96	श्री आबिद हुसैन	बोकारो	अग्रणी जिला प्रबंधक	8451978491
97	श्री देवव्रत शर्मा	चतरा	अग्रणी जिला प्रबंधक	8002738027
98	श्री अमित कुमार	धनबाद	अग्रणी जिला प्रबंधक	8298715715
99	श्री संतोष कुमार	पूर्वी सिंहभूम	अग्रणी जिला प्रबंधक	7260814454
100	श्री सूर्यनारायण मोहंती	गिरिडीह	अग्रणी जिला प्रबंधक	7488060045
101	श्री पवन कुमार	गुमला	अग्रणी जिला प्रबंधक	8879743105
102	**अनुपस्थित**	**हज़ारीबाग**	**अग्रणी जिला प्रबंधक**	
103	श्री सनत दुबे	खूंटी	अग्रणी जिला प्रबंधक	9661859585
104	श्री निवास कुमार	कोडरमा	अग्रणी जिला प्रबंधक	9534741185
105	श्री नेवन्दु कुमार	लोहरदगा	अग्रणी जिला प्रबंधक	8177819118
106	**अनुपस्थित**	**रामगढ़**	**अग्रणी जिला प्रबंधक**	
107	श्री संजीव कुमार चौधरी	रांची	अग्रणी जिला प्रबंधक	7903780946
108	श्री बीरेंद्र कुमार शिट	सरायकेला खरसावां	अग्रणी जिला प्रबंधक	9572024420
109	श्री कार्तिक अनुराग मिंज	सिमडेगा	अग्रणी जिला प्रबंधक	7362843027
110	श्री दिवाकर सिन्हा	पश्चिम सिंहभूम	अग्रणी जिला प्रबंधक	8936802753
111	श्री चन्द्रशेखर पटेल	दुमका	अग्रणी जिला प्रबंधक	9074485076
112	श्री चंदन चौहान	गोड्डा	अग्रणी जिला प्रबंधक	7781919295
113	श्री राजीव कुमार	देवघर	अग्रणी जिला प्रबंधक	7992310119
114	श्री ए के मांझी	गढ़वा	अग्रणी जिला प्रबंधक	9934363709
115	श्री राजेश कुमार सिन्हा	जामताड़ा	अग्रणी जिला प्रबंधक	9470650026
116	श्री राजीव कुमार मंदिलवार	लातेहार	अग्रणी जिला प्रबंधक	7781011677
117	श्री मनोज कुमार	पाकुर	अग्रणी जिला प्रबंधक	9771438410
118	श्री एंथोनी लियांगी	पलामू	अग्रणी जिला प्रबंधक	9934363710
119	श्री सुधीर कुमार	साहिबगंज	अग्रणी जिला प्रबंधक	9771438409
120	श्रीमती सुनीता कुमारी	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
121	श्रीमती एकता उपाध्या	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
122	श्री रोशन चौधरी	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	8712252343
123	श्रीमती प्राची मिश्रा	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	9931399824
124	श्री लॉरेंस अल्फ्रेड बोइपाई	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
125	श्री दीपक	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	
126	श्री कुमार ऋषव	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	9525166838
127	श्री प्रशांत कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	9471182910
128	श्री शैलेश कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	8005958455
129	श्री बिट्टू कुमार	राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति	बैंक ऑफ इंडिया	